DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

NEW DELHI
MONDAY
NOVEMBER 21, 2022

Unauthorised colony residents say ownership rights still a pipe dream

Risha Chitlangia
Risha.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: While the Bharatiya Janata Party (BJP) is projecting the Centre's move to allot flats to slum residents as its key achievement, it faces a tough task ahead of the municipal elections to address the concerns of residents of unauthorised colonies who are yet to get ownership rights under the PM-Uday scheme. Residents of these colonies say the BJP's "unfulfilled promises" are going to be a key issue in the upcoming polls.

The central government launched the Prime Minister-Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-Uday) in December 2019, just before the Assembly elections in 2020.

Its purpose was to give ownership rights to residents of 1,731 unauthorised colonies in Delhi after the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019, was passed by Parliament.

While the central government began the process to grant rights, the Delhi Development Authority (DDA), the nodal agency for the scheme's implementation, had to stop the process in 80 unauthorised colonies that fall in the 'O-zone', where construction is banned, according to Master Plan of Delhi-2021.

Anil Sharma, a resident of Jaitpur, an unauthorised colony, who has formed an association to pursue the matter with the DDA, said, "It is going to be three years in December and the Centre has not been able to address this issue till now. We invested time and money in starting the process to get the survey done and preparing documents. But the process was stopped midway in 2020 and we don't know when it is going to start." He added, "People voted for BJP last time as it promised to give ownership rights. This is going to be one of the main issues this time."

> We will ask all parties about their stand. We want a commitment... For us, this is the most important issue in these elections
>
> **SANTOSH MISHRA,** Chhatarpur Extension RWA

> The Centre has taken measures to address the issue in the new Master Plan of Delhi-2041, which will be notified soon.
>
> **HARISH KHURANA,** Delhi BJP spokesperson

Like Jaitpur, there are many unauthorised colonies in Badarpur, Okhla and Karawal Nagar, where residents have been waiting to get ownership rights.

Delhi BJP spokesperson Harish Khurana said, "The central government is committed to giving ownership rights to residents of all 1,731 unauthorised colonies. The Centre has taken measures to address the issue in the new Master Plan of Delhi-2041, which will be notified soon. Residents will get ownership rights. We gave flats to slum residents recently. We deliver on our promises."

However, even in the list of 1,731 colonies, 69 unauthorised colonies were not included, such as Chattarpur Extension and Sainik Farms, since these are considered "affluent". Residents of these 69 colonies say that ownership rights are going to be a key poll issue.

Raman Aggarwal, president of the welfare association of 69 unauthorised colonies, mainly located in south Delhi areas such as Deoli, Khanpur, Chattarpur, Khirki Extension, Mehrauli, Mahipalpur and Bijwasan, said, "For past three years, we have approached all government agencies to address our issue. When PM-Uday was launched, we were told that our colonies will be taken up in later stages. Three lakh people live in these 69 colonies. When the government is giving ownership to others, then why not to us? This going to be a key poll issue."

BJP leaders admit that voters in these 69 unauthorised colonies as well as the 80 colonies in the 'O-zone' play a decisive role in as many as 40 municipal wards. With the BJP hoping to win a fourth term in the unified Municipal Corporation of Delhi, the party will have to address the concerns of these residents.

Santosh Mishra, general secretary of Chattarpur Extension residents' welfare association, one of the 69 colonies, said, "We will ask all political parties about their stand on the issue. We want a commitment from them that the matter will be resolved in a time-bound manner. For us, this is the most important issue in these elections. We recently held a meeting with residents of all 69 colonies in this regard."

BJP MLA Ramvir Singh Bidhuri, Leader of the Opposition in the Delhi Assembly, said, "The Centre has taken measures to address the issue faced by 'O-zone' colonies. The process under PM-Uday will soon start in these colonies. As far as affluent colonies are concerned, we have taken up the matter with the central government."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 नवंबर, 2022 DATED

राजधानी की सूरत बिगाड़ रहा अवैध निर्माण, ले रहा जान

निहाल सिंह • नई दिल्ली

अवैध निर्माण न केवल राजधानी की सूरत बिगाड़ रहा है, बल्कि लोगों की जान भी ले रहा है। हर वर्ष अवैध निर्माण के चलते कई लोगों की जान जाती है। अधिकृत से अनधिकृत कालोनियों में अवैध निर्माण की समस्या है। परेशानी यह है कि अवैध निर्माण कर दिल्ली में कालोनियां बसने की रफ्तार भी नहीं थम रही है। बाहरी दिल्ली के जिन इलाकों में खेती की जमीन हैं वहां पर अवैध निर्माण कर कालोनियां काटी जा रही हैं और यहां पर अवैध निर्माण कर बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करता है। यदि प्रशासन ने सख्ती दिखाता तो अवैध कालोनियों की संख्या 1731 नहीं पहुंचती।

बड़ा मुद्दा

शास्त्री पार्क में अवैध निर्माण करके बनाए गए मकान • जागरण

आवास की कमी से हो रहा है अवैध निर्माण: दिल्ली में आवास की बहुत बड़ी समस्या है। आज से 20 25 वर्ष पहले जो खाली जगह थीं, उन पर कालोनियां बसनी शुरू हुई और बीते 10 साल में वह कालोनियां बहुमंजिला इमारतों के रूप में खड़ी हो गईं। इसकी बड़ी वजह दिल्ली में अधिकृत कालोनियों में किफायती आवास न होना है। अनाधिकृत कालोनियों में पांच से छह मंजिला मकान बनकर खड़े हो जाते हैं। इसमें लोग परिवार की जरूरतों के हिसाब से मकानों को बना लेते हैं तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो किराये के हिसाब से मकानों को बना रहे हैं। यही वजह है कि पहले खाली प्लाट पर मकान बने, फिर ऊंची-ऊंची इमारतें बनीं और अब इन मकानों को तोड़ फ्लैट नुमा बनाने की शुरुआत हो चुकी है। कई कालोनियों में तो अभी तक पानी और सीवर की लाइन तक नहीं पहुंची है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बीते वर्षों में जो हाउसिंग स्कीम लांच की है, वह इसलिए भी पूरी तरह सफल नहीं हुई है, क्योंकि एक तो उन आवासीय कालोनियों में प्राथमिक सुविधाएं तक नहीं थीं और फ्लैट की कीमत भी इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने इन्हें खरीदने में रुचि तक नहीं दिखाई।

प्रशासन की है मिलीभगत: अवैध निर्माण में दिल्ली पुलिस से लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी संलिप्त हैं। कई बार जांच एजेंसियां अवैध निर्माण के लिए रिश्वत लेते हुए इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ती है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली पुलिस को बार-बार यह स्पष्ट करना पड़ता है कि अवैध निर्माण में किसी पुलिसकर्मी की कोई भूमिका परोक्ष और अपरोक्ष तौर पर नहीं है। बावजूद इसके पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार के मामले अवैध निर्माण को लेकर सामने आते रहते हैं। इसी प्रकार नगर निगम के भवन विभाग में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों पर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने और उन पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगते रहते हैं। इतना ही नहीं कई बार एजेंसियों की कार्रवाई में अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े गए हैं।

अवैध निर्माण बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक व्यावसायिक अवैध निर्माण है। चांदनी चौक को ही देख लें, रोजाना यहां दिन रात अवैध निर्माण हो रहा है, रोक इसलिए नहीं लग पा रही कि इसमें राजनेताओं से लेकर अधिकारियों की मिलीभगत है। इसे रोके जाने की जरूरत है, क्योंकि पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हुई है जो लोगों की जान ले चुकी है। -मुदित अग्रवाल, प्रवक्ता, कांग्रेस

अवैध निर्माण को रोकने के लिए जरूरी है कि जनता अपना पार्षद ईमानदार चुने। साथ ही प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। अब पीएम उदय योजना आने के बाद यह कालोनियां डीडीए के अधीन चली गई हैं। ऐसे में निगम का इससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। -अनिल लाकड़ा, पूर्व नेता विपक्ष, आप

हर साल अवैध निर्माण के चलते लोगों की चली जाती है जान, अवैध निर्माण के चलते बस गई हैं 1731 अवैध कालोनियां

केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1731 कालोनियों को पीएम उदय योजना के तहत नियमित कर दिया है। अब जो लोग पीएम उदय योजना के तहत अपने मकान का मालिकाना हक ले लेंगे तो वहां नक्शे पास होने लगेंगे। इससे बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। पर दिक्कत यह है कि छज्जा और छोटे-छोटे लालच के चक्कर में लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजली पानी का कनेक्शन कट जाता है। -श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्व महापौर व भाजपा नेता

11,238	संपत्तियां अवैध निर्माण के लिए की गई है चिह्नित
173	संपत्तियों को अवैध निर्माण के चलते सीलिंग के दिए गए हैं आदेश
879	संपत्तियों में अवैध निर्माण के लिए जारी किए गए हैं आदेश
2,834	संपत्ति मालिकों को दिया गया है नोटिस
2,691	संपत्तियों को अवैध निर्माण के कारण सील किया गया
4,662	संपत्तियों को अवैध निर्माण के कारण गिराया गया
627	मामले कार्रवाई के लिए विभिन्न न्यायालयों में हैं लंबित

कब-कब हुए हादसे

- 25 अप्रैल 2022 सत्या निकेतन में इमारत गिरी, पांच घायल
- 24 जुलाई 2022 मुस्तफाबाद में इमारत गिरी, एक मौत, छह घायल
- 9 सितंबर 2022 आजाद मार्केट में निर्माणाधीन इमारत गिरी, तीन की मौत
- 8 अक्टूबर 2022 फराश खाना में इमारत गिरी, चार की मौत
- 7 अगस्त 2021 दो मंजिला इमारत गिरी, तीन घायल
- 10 जून 2021 पंचशील पार्क में छज्जा गिरा, एक की मौत
- 17 फरवरी 2020 चितरंजन पार्क में निर्माणाधीन इमारत गिरी, एक की मौत
- 2 सितंबर 2019 सीलमपुर में चार मंजिला इमारत गिरी, दो की मौत
- 24 जुलाई 2019 नबी करीम में चार मंजिला इमारत गिरी
- 18 जून 2019 सदर बाजार में प्रेस वाली गली में इमारत का हिस्सा गिरा

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
NAME OF NEWSPAPERS---- नई दिल्ली, सोमवार, 21 नवंबर 2022 ----DATED----

मूलभूत सुविधाओं को तरस रहीं कच्ची कॉलोनियां

मेरी आवाज सुनो
समस्या: कच्ची कॉलोनियां

दिल्ली नगर निगम चुनाव में अनधिकृत कॉलोनियों का विकास प्रमुख मुद्दा है। राजधानी में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिनमें दिल्ली की 40 प्रतिशत आबादी यानी करीब 50 लाख लोग रहते हैं। लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों में कच्ची कॉलोनियों का जाल है। निगम पार्षदों के पास इनमें विकास कार्य कराने की इजाजत नहीं होती है। इन्हें नियमित करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कॉलोनियों को नियमित न कर वहां रहने वाले लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक देने की सुविधा दी गई है। लोगों का कहना है, नेता वादे तो करते हैं, लेकिन नहीं। सीवर, पानी, सफाई आदि समस्याओं से लाखों लोग जूझ रहे हैं...

विकास कार्यों के लिए बजट की बड़ी समस्या

दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों के विकास के लिए बजट प्रमुख मुद्दा है, लेकिन निगम के पास इनमें लगाने के लिए बजट नहीं होता है। दिल्ली सरकार ने दो साल पहले बजट में कच्ची कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, ताकि मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें। वहीं, जल बोर्ड की ओर से लगभग एक हजार करोड़ की लागत से इनमें पाइपलाइन डालने की योजना पर काम शुरू किया गया।

1993 के बाद एक भी कॉलोनी नियमित नहीं हुई

वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव से महज सालभर पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. शीला दीक्षित ने वादा किया था कि जिन कॉलोनियों को अस्थायी नियमन प्रमाण पत्र मिल गए थे, उन्हें स्थायी रूप से नियमित किया जाएगा।

उसके बाद दिल्ली प्रदेश की सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी ने 2015 में विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का भी वादा किया था। इस तरह कई चुनाव आए और हर बार चुनाव के ही मौके पर कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा हुई, पर वास्तविकता यह है कि 1993 के बाद एक भी कॉलोनी नियमित नहीं हुई।

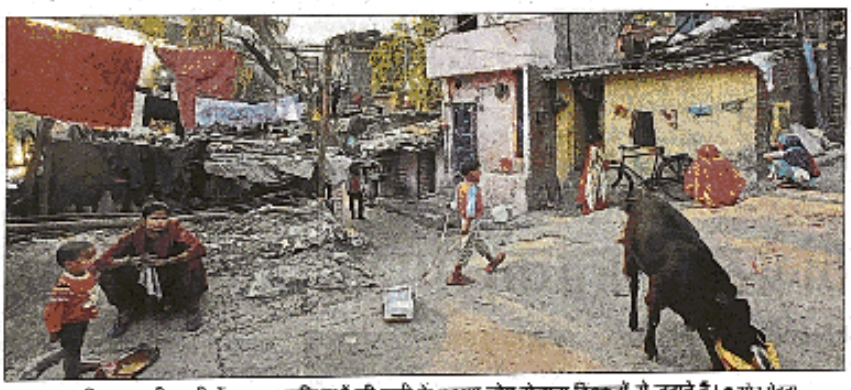

अन्ना नगर स्थित कच्ची बस्ती में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोग रोजाना दिक्कतों से जूझते हैं। • सोनू मेहता

दो श्रेणियों में विभाजित

अनधिकृत कॉलोनियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में सरकारी और ग्राम सभा की भूमि पर बसी कॉलोनियां हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में निजी जमीन पर बसी कॉलोनियां। ग्राम सभा की भूमि पर बसी कॉलोनियों को शहरीकृत गांवों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अहम बात यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ही इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। साथ ही इनमें विकास के मानक भी तय करेगा। खाली जमीन चिह्नित कर वहां पार्क तथा सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएगा।

50 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, 30 विधानसभा क्षेत्र इन कॉलोनियों में आते हैं

सात सौ एकड़ में बस्तियां

दिल्ली की अधिकांश अनधिकृत कॉलोनियों में आधुनिक तो दूर की बात मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रहीं। अनधिकृत कॉलोनियों में बनीं अवैध झुग्गियां भी यहां के निवासियों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न इलाकों में करीब 700 एकड़ में झुग्गी बस्तियां हैं और इनमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं।

ये हैं प्रमुख विधानसभा क्षेत्र

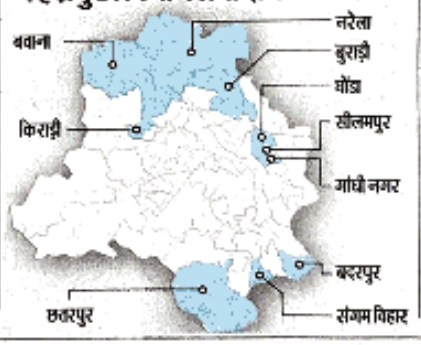

प्रमुख समस्याएं

- पानी और सीवर लाइनें न होना
- मकानों के नक्शे पास न होना
- सामुदायिक सेवाएं न होना
- गलियों और सड़कों का निर्माण न होना
- स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव

हमारे माथे पर एक दाग है कि हम कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। कोई भी सरकार यह दाग नहीं हटा पाई है। सिर्फ वादे किए जाते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। - शराफत अली, घोंडा

हमारी कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या सीवर और पानी की है। बारिश के मौसम में घरों-गलियों में पानी भर जाता है। किसी भी पार्टी ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ चुनाव में वादे किए गए। -अफजल खान, घोंडा

हमने 90 के दशक में 17 अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर संघर्ष किया था, लेकिन आज भी कई सुविधा नहीं हैं। बरसात में गलियां तालाब में बदल जाती हैं। - पं. विष्णु दत्त शर्मा, अनधिकृत कॉलोनी समिति बदरपुर के अध्यक्ष

कच्ची कॉलोनियों में जितना विकास होना चाहिए था, वह अभी भी नहीं हो सका है। कई योजनाएं धरातल पर नहीं उतरीं। केंद्र को इस ओर कदम उठाना चाहिए। - अनिरुद्ध शर्मा लाला, मोतड़बद विस्तार

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI NOVEMBER 20, 2022 ---DATED----------

'Carpet-bomb' drive: BJP plans 14 roadshows today

TIMES NEWS NETWORK

Sunday's high-pitch campaign will feature BJP chief JP Nadda, Union defence minister Rajnath Singh and the CMs of Himachal Pradesh, Assam and Uttarakhand

New Delhi: BJP will conduct a "carpet-bomb" campaign for the Municipal Corporation of Delhi elections. There are 14 road shows lined up for Sunday featuring BJP president JP Nadda, Union defence minister Rajnath Singh and the chief ministers of Himachal Pradesh, Assam and Uttarakhand. The high-pitch campaign will continue till the MCD polls on December 4 and will involve prominent faces, including Union ministers and CMs.

Terming it the Vijay Sankalp road shows, BJP Delhi general secretary Kuljeet Singh Chahal said on Saturday that the MCD polls were not ordinary elections, but an opportunity for Delhi's citizens to clean up political corruption.

BJP spokesperson Harish Khurana similarly said the leaders would make people aware "of the corruption in AAP". He said, "They will also tell the people about the flats given to them by Prime Minister Narendra Modi." Earlier this month, Modi had inaugurated 3,024 new flats for economically weaker section residents as part of an in-situ slum rehabilitation in Delhi.

While Nadda will canvass votes in Sangam Vihar and Rajnath Singh in Uttam Nagar, Bhojpuri singer and newly elected MP from Azamgarh, Dinesh Lal Yadav, will be part of the road show at Khyala. Delhi MPs Meenakshi Lekhi, Harsh Vardhan, Manoj Tiwari, Ramesh Bidhuri, Parvesh Sahib Singh Verma, Gautam Gambhir and Hansraj Hans will also join the road show.

The Delhi BJP leadership had requested over 60 senior central functionaries, among them Union home minister Amit Shah and UP CM Yogi Adityanath, to campaign in Delhi.

State president Adesh Gupta said in the coming days, the campaigners would visit metro stations, bus stands, parks and other places to spread awareness of the work done by the BJP-ruled corporation and BJP members during the Covid crisis. State BJP vice-president Virendra Sachdeva added that the focus would be on neighbourhood gatherings, the aim being to reach the common people through small meetings deep in the localities.

BJP has been at the helm of the three erstwhile municipal corporations in Delhi since 2007. This year, it is pitted in a keen contest for control of the municipal body with AAP and Congress. In the last municipal elections in 2017, BJP won 181 of the 272 wards, routing its rivals, with the AAP managing to win a mere 48 wards and Congress 30.

After the BJP-led central government unified the three corporations into one single municipal corporation this year, the number of wards has been reduced from 272 to 250.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- पंजाब केसरी दिल्ली, सोमवार / 21.11.2022 ---ATED----

दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्किंग समस्या बनीं प्रमुख मुद्दा

नेताजी जरा सुनिए! सवा लाख करोड़ वाहनों पर सिर्फ एक लाख की पार्किंग

प्रगनेश सिंह

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : राजधानी दिल्ली में चुनाव कोई भी हो, उसमें वाहनों की पार्किंग प्रमुख मुद्दा बनता रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली में एक करोड़ वाहनों पर बमुश्किल सवा लाख वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है। यही कारण है न सिर्फ दिल्ली में रोजाना जाम की समस्या रहती है, बल्कि पार्किंग माफिया भी काफी सक्रीय हो जाते हैं। ऐसे में दिल्लीवासी को उम्मीद है कि इस बार निगम चुनाव के बाद उन्हें पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि दिल्ली पार्किंग की व्यवस्था कराए जाने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली मेट्रो सहित अन्य कई विभागों की है। इसमें सबसे ज्यादा निगम के पास रहता है। जानकारी के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा प्रतिदिन औसतन 1200 से 1500 वाहनों का पंजीकरण किया जाता है। अबतक दिल्ली में कुल 1 करोड़ 20 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण किया जा चुका है। लेकिन इनके पार्किंग की व्यवस्था नाम मात्र है। बता दें कि इसमें दोपहिया वाहनों साथ मालवाहक और चार पहिया वाहनों को शामिल किया गया है।

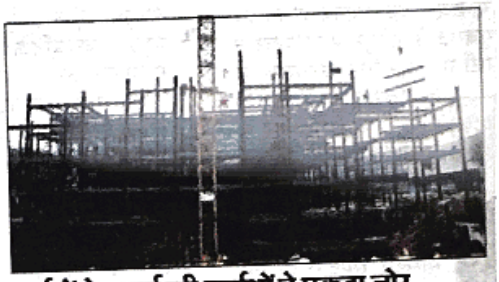

पार्षदों के कार्य की चर्चाओं ने पकड़ा जोर

निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिए हैं वार्ड की जनता ने भी अपना आकलन शुरू कर दिया है। दुकानों, चाय की नुक्कड़ और पार्कों में बैठे लोग पार्षद के वादों और कार्यों का आकलन करना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर लोग पार्किंग को लेकर आपति जताते नजर आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा समस्या करोल बाग और चादनी चौक का आ रहा है। यहां पर लोगों का कहना है कि आधिकारिक पार्किंग नहीं होने की वजह से पार्किंग माफिया काफी सक्रीय रहते हैं, लिहाजा वाहन मालिकों को पार्किंग के लिए काफी रकम चुकानी पड़ती है।

3324 वाहनों की पार्किंग क्षमता बढ़ेगी...

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में करीब 6 पार्किंग साइड का निर्माण कार्य चल रहा है। जो दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 3324 वाहनों की पार्किंग करने की व्यवस्था रहेगी। हालांकि उक्त 6 पार्किंग साइड के निर्माण से अधिक राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि दिल्ली में रोजाना पंजीकरण हो रहे आंकड़ों के मुताबिक, यह काफी कम हैं।